



विश्व का एक मात्र एल्बिनो जाएंट एन्टिडोर जंगल में खूब फल फूल रहा है। एल्विन नाम का यह एन्टिडोर पहली बार गत वर्ष देखा गया था और हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं। माना जाता है कि, यह एक साल का है। एन्टिडोर एण्ड हाईवे प्रोजेक्ट (ए.एच.पी.) के शोधकर्ताओं ने 2022 दिसम्बर को इसे ब्राजील के मातो ग्रोसो दो सूल राज्य के एक बाड़े में देखा था, उन्होंने ही इसे एल्विन नाम दिया। ब्राजील के वाइल्ड एनिमल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट द्वारा शुरु किए गए प्रोजेक्ट का लक्ष्य था एन्टिडोर और वाहनों की टक्कर का आकलन करना। वैज्ञानिकों ने जब पहली बार इसे देखा था उस समय यह अपनी सामान्य रंग की मां की पीठ पर चढ़ा हुआ था। दस माह से कम उम्र के एन्टिडोर इसी तरह अपनी मां की पीठ पर चढ़े रहते हैं। टीम ने एल्विन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उसके ऊपर जी.पी.एस. सिस्टम लगाया। हाल ही में दस मई को वैज्ञानिकों ने एल्विन की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कीं। एल्विन का वजन 14 किलो और लम्बाई डेढ़ मीटर बताई गई है। इसका अर्थ है कि, वह एक साल से ऊपर का है और जल्दी ही पूर्ण वयस्क हो जाएगा। एल्विन का पुराना जी.पी.एस. सिस्टम भी छोटा हो गया है इसलिए उसे नया जी.पी.एस. सिस्टम पहनाया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि, अगस्त 2021 में उन्हें इसी क्षेत्र में एक अन्य अवयस्क नर एल्बिनो जाएंट एन्टिडोर का शव मिला था। शव की हालत से लग रहा था कि, उसका शिकार किया गया है। टीम उस एल्बिनो के डी.एन.ए. की तुलना एल्विन के डी.एन.ए. से करेगी ताकि पता चले कि उनके बीच कोई प्रत्यक्ष रिश्ता है या नहीं। अगर नहीं तो इससे यह संकेत अवश्य मिलेगा कि, अन्तः प्रजनन के कारण इनका जिन पूल घट गया है, इसलिए एल्बिनिज़्म जैसी दुर्लभ विकृति नज़र आने लगी है।

## सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो और जज

नयी दिल्ली, 5 जुलाई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस वेंकटरारायणन भट्टी को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। शीर्ष

■ कोलीजियम ने तेलंगाना और केरल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति एस वेंकटरारायणन भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की।

अदालत की ओर से जारी एक बयान में दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नत करने की सिफारिश करने के फैसले से संबंधी जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनाने के लिए सिफारिश करने संबंधी फैसला मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सुर्य कांत की कॉलेजियम की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया।

## कैप्टन अमरिंदर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पार्टी उन्हीं कांग्रेस से निष्कासित कर दिये जाने के बाद बनाई थी। भाजपा सूत्रों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनका नाम विचारार्थीन है। ज्ञातव्य है कि इस पद को 2020 से मनोज सिन्हा सँभाले हुये हैं। सूत्रों ने कहा कि मोदी दो-तीन राज्यपालों को उनके पद से हटाकर लोकसभा चुनावों में खड़ा कर सकते हैं। इन राज्यपालों में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (71) भी शामिल हैं। चूँकि जो कुछ मोदी के दिमाग में चल रहा होता है, उसे वे किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, इसलिए यह सोचकर पार्टी नेता ऐसी बातों पर मायापन्थी नहीं करते कि वे कहीं मोदी के कापभानन ने बन जायें।

सूत्रों ने कहा कि कैप्टन को ऐसा संकेत दिया गया था कि भाजपा पंजाब में कुछ लोकसभा सीटें पाने के लिये उन पर भरोसा करेगी। लेकिन उन्होंने उस समय स्वयं को तिरस्कृत महसूस किया। जब पंजाब का भाजपाध्यक्ष पद सुनील जाखड़ को दे दिया गया। कांग्रेस से आए जाखड़ कांग्रेस के पुराने नेता तथा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के बेटे हैं। सूत्रों ने कहा कि मोदी अमरिंदर सिंह को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाकर, उन्हें सौलतना देने की कोशिश कर रहे हैं।

## शरद पवार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) शरद पवार गुट ने 3 जुलाई को चुनाव आयोग के समक्ष केवियट प्रस्तुत किया था यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह प्रतिद्वंदी अजीत गुट की अपील के आवेदन पर एकरतफा सुनवाई न करे। चुनाव आयोग को अजीत गुट का 30 जून को लिखा पत्र 5 जुलाई को मिला जिसमें दावा किया गया है कि उसमें पार्टी के 40 विधायकों एवं सांसदों के हस्ताक्षर हैं। आयोग ने यह पत्र "विवादित मामला" मानते हुए शरद पवार को उनके जवाब के लिए भेजा है।

# 'कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए एन.आई.ए.'

एन.आई.ए. मामलों की विशेष अदालत ने आरोपियों की याचिका पर यह निर्देश दिया है

जयपुर, 5 जुलाई (का.सं.)। एन.आई.ए. (नैशनल इन्वैस्टिगेशन एजेंसी) मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में एन.आई.ए. को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपियों को इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए। कोर्ट ने कहा है कि एन.आई.ए. दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड व डी-86 के साथ दी गई सीडी व मोबाइल मैसेज, जिस डिवाइस में स्टोर किए गए थे उसकी कॉपी उन्हें दे दे। कोर्ट ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अतारी सहित मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, आसिफ, वसीम

■ आरोपियों ने कहा था कि, उन्हें मृतक कन्हैयालाल की दुकान की सी.सी.टी.वी. फुटेज, फोटो व आवाज के नमूने उपलब्ध कराए जाएं। कोर्ट ने रंगीन फोटो दिलवाने की आरोपियों की प्रार्थना खारिज कर दी।

अली, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम खान के प्रार्थना पत्र पर दिया। वहीं कोर्ट ने आरोपियों की मौके के रंगीन फोटोग्राफ दिए जाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

आरोपियों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि उन्हें मृतक कन्हैयालाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज व फोटो और अनुसंधान के दौरान

आरोपी मुस्लिम खान, मोहम्मद रियाज अतारी व गौस मोहम्मद की आवाज के जो नमूने लिए थे उनकी सीडी दिलवाई जाए। इसके जवाब में एन.आई.ए. के विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश शर्मा ने कहा कि आरोपियों को रंगीन फोटोग्राफ मुहैया कराना संभव नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग आरोपी आगामी पेशियों में कर सकते हैं। वहीं दस्तावेज

## महाराष्ट्र व गोवा, कर्नाटक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उचित एवं आवश्यक महत्व देना ही चाहिये। अर्थशास्त्री राज्य के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन पर दुख व्यक्त करते रहते हैं तथा कहते हैं कि इस मुद्दे पर जितना जल्दी विचार कर लिया जाये, उतना ही श्रेयस्कर होगा।

अगर व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों को भयबुर किया गया तो उन्हें निश्चित रूप से अन्य विकल्पों की तलाश करनी ही होगी। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज (एफ.के.सी.सी.आई.) के अध्यक्ष बी. विजय कुमार ने कहा, "मैं नहीं मानता कि कोई उद्योग राज्य से बाहर चला जायेगा, और अगर किसी ने ऐसे बयान दिये हैं, तो वे किसी क्षण के तात्कालिक आवेश में दे दिये गये होंगे।" जो भी है, लेकिन कर्नाटक के लोगों की औद्योगिक इकाइयों तमिलनाडु के होसूर नगर में तथा महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में हैं।

बिजली की दरें बढ़ने की स्थिति को लेकर औद्योगिक प्रतिष्ठान दोनों ही काम कर रहे हैं - वे जहाँ राज्य सरकार के साथ भी लामबंदी कर रहे हैं, वहीं वे विरोध

करने के लिये सड़क पर उतर आये हैं तथा बिजली दरों में एकाएक हुई बड़ी वृद्धि, जिसके कारण राज्य में उद्योग संचालित करना मुश्किल हो गया है, को वापस लेने की माँग कर रहे हैं।

उद्योगपतियों के एक गुट में भावना है कि ऊर्जा लागत में वृद्धि कृषकों और परिवारों को मुक्त बिजली के लिए अनुदान जुटाने को की गई है। मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने पहले ही ऊर्जा शुल्क में संशोधन की माँग टुकरा दी है।

मुख्यमंत्री रविवार को कहा कि सरकार को उद्योग की परेशानी का पता है और उसका विश्वास जीतने के प्रयास किए जाएंगे। उद्योग जगत इससे प्रभावित नहीं हुआ और कल बंद का आ आन किया और उत्तर कर्नाटक सहित कई भागों में मार्च भी निकाला गया। बंद का आ आन कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया था और विभिन्न क्षेत्रों के चैम्बर इसमें शामिल हुए। हुबली और धारवाड़ से प्राप्त खबरों के अनुसार वहाँ औद्योगिक इकाइयों सूनी पड़ी हैं। हुबली में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अधिक वृद्धि से उद्योग चलाना मुश्किल हो जाएगा।

## पेत्रियार नदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तो लड़ने लगेंगे। जस्टिस बोपन्ना कर्नाटक से और जस्टिस सुंदर तमिलनाडू से हैं।

तमिलनाडू द्वारा 2018 में दायर किए गए इस मुकदमे में एक संक्षिप्त शपथ पत्र पेश करते हुए जलशक्ति मंत्रालय ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत पेत्रियार जल विवाद टिब्यूलन का गठन करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडलीय सचिवालय और केन्द्रीय मंत्रिमंडल को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अभी इसमें अंतिम निर्णय लेना है।

तमिलनाडू सरकार अपने मूल क्लेम के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जो उक्त नदी पर चैक डैम्स बनाने व जल प्रवाह का रूख मोड़ने के खिलाफ दर्ज किया था। तमिलनाडू सरकार ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय नदी एक राष्ट्रीय सम्पदा है और कोई राज्य इस पर एकाधिकार नहीं जता सकता। उसने कहा कि 1892 का नदी जल समझौता संबंधित राज्यों पर लागू है और कर्नाटक बिना तमिलनाडू की स्वीकृति के चैक डैम्स और जल मार्ग परिवर्तन का निर्माण नहीं कर सकता।

# देवली में एक बार फिर बुजुर्ग दंपत्ति से लूट की वारदात

बेखौफ लुटेरों ने 75 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति व एक अन्य महिला के सोने चांदी के आभूषण लूटे

देवली, 5 जुलाई (निर्स)। इन दिनों लगातार लूट और चोरी की वारदातों के बढ़ते मामलों से लोगों में यहां भय बना हुआ है। इतनी वारदातें हो रही हैं लेकिन एक भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस चोरों का सुराग लगा पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। लूट और चोरी की बढ़ती वारदातों से यहां चोर और लुटेरों में पुलिस का भय मानो जैसे पूरी तरह समाप्त हो गया है।

शहर के गणेश रोड स्थित अग्रसेन स्कूल में रह रहे दंपति व उनकी बहन जिनके साथ मंगलवार रात 12 बजे अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात की अंजाम दिया। बेखौफ लुटेरों ने सबसे पहले तीनों जनों को बुरी तरह से पीटा, उसके बाद उनके शरीर पर पहने और घर में रखे सोने और चांदी के आभूषण लूट कर ले गए।

पीड़ित मोहन लाल मीणा ने बताया कि, वह स्वयं उनकी पत्नी मोत्या देवी व बहन मथरा देवी अग्रसेन स्कूल के

■ लुटेरों ने पीट-पीटकर वृद्ध महिला की कलाइयां तोड़ दीं।

मुख्य गेट स्थित पोर्च में सो रहे थे। इस दौरान स्कूल के दाईं ओर से अज्ञात तीन बदमाश आए जिन्होंने आते ही उन पर सोते हुए लाठियों से हमला कर दिया। पीड़ित वृद्ध दंपति ने बताया कि, बदमाशों ने सबसे पहले उनका गला दबा दिया तथा सिर पर ईंट की दे मारी। इसके बाद पीड़ित अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। वहीं एक अन्य जने ने पीड़ित की बहन मथरा देवी की कलाइयों पर लकड़ी से कई बार वार किए और दोनों हाथों की कलाई को बुरी तरह से जखमी कर दिया। इससे मथरा देवी की कलाइयां टूट गईं। इसी तरह बेखौफ लुटेरों ने मोत्या देवी के सिर व गले पर भी वार किया और उन्हें बुरी तरह घायल कर लूट की वारदात को अंजाम दिया।

उल्लेखनीय है कि, इन दिनों शहर और आसपास के क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्र और अन्य स्टेट के अनजान लोग यहां पर आकर रह रहे हैं। यहां रह रहे अन्य राज्यों और बाहरी क्षेत्र के लोगों का पुलिस द्वारा सत्यापन शायद नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार औद्योगिक इकाई और बांध में तालाबों में मत्स्य कार्यों के लिए भी यूपी-बिहार आसाम इत्यादि क्षेत्रों से मजदूर वर्ग के लोग यहां आए हुए हैं जो शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में किराए के मकान लेकर रह रहे हैं। यहां देखने वाली बात तो यह है कि, मकान मालिकों द्वारा भी उक्त किरायेदारों की जानकारी पुलिस तक की नहीं दी जाती है और पुलिस को भी बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की जांच वे सत्यापन करते हुए कभी नहीं देखा गया है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि, वह देवली शहर एवं आसपास के क्षेत्र में रहने वाले बाहरी लोगों की जांच पड़ताल कर उनका सत्यापन करना चाहिए। ताकि लूट चोरी जैसी बढ़ती वारदातों को

अंजाम देने वाले अपराधियों तक कानून का हाथ पहुंच सके। वृद्ध दंपति ने बताया कि, अज्ञात बदमाशों ने उनकी बहन का सोने का मांदलिया व चांदी की पायजेब तथा इसी तरह उनकी पत्नी मोत्या देवी की चांदी की पायजेब व सोने का मांदलिया लूटकर ले गए। सोने के आभूषण आधा-आधा तोले के थे, जबकि पायल 250-250 ग्राम वजन थी।

## ए.आई.सी.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की उम्मीद है। इस मॉटिंग में राहुल गांधी के उपस्थित होने की भी संभावना है, जबकि गलहोत ज़ूम पर रहेंगे क्योंकि उनके दोनों टोंगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि दिन की समाप्ति तक कोई समाधान सामने आ जायेगा क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तथा समय एवं धैर्य चुकता जा रहा है।

# मोदी राजस्थान सहित चार राज्यों को देंगे 50 हजार करोड़ रु. की सौगात

प्र.मंत्री मोदी 8 जुलाई को बीकानेर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे

नयी दिल्ली, 5 जुलाई (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को चार राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के दौर पर जायेंगे जहां वह लगभग 50,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गौरतलब है कि, राजस्थान में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यहां भाजपा नेताओं का आवागमन तेज हो गया है। इसी सप्ताह अमित शाह और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा हो ही चुका है। प्रधानमंत्री 8 जुलाई को सुबह तेलंगाना के वारंगल पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वह विभिन्न परियोजनाओं की

■ गौरतलब है कि, राजस्थान में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यहां भाजपा नेताओं का आवागमन बढ़ गया है। इसी सप्ताह अमित शाह और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा हो ही चुका है।

आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शाम को बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वह राजस्थान की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। वह 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। रायपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और

लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वह गीता प्रेस, गोरखपुर के शताब्दी समारोह के समान समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

# 'पैट्रोल की कीमत 15 रु. तक हो सकती है'

प्रतापगढ़/ नई दिल्ली, 5 जुलाई। प्रतापगढ़ में मंगलवार को हुये एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने दावा किया है कि, जल्द ही देश में पेट्रोल सिर्फ 15 रुपए प्रति लीटर मिल सकेगा।

दरअसल, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के प्रतापगढ़ में मंगलवार को हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता भी बनेगा। ये हमारी सरकार की सोच है। गडकरी ने इस कार्यक्रम में कहा, अब सब गाड़ियां किसानों के तैयार किए इथेनॉल से चलेंगी। 60 प्रतिशत इथेनॉल और 40 प्रतिशत बिजली, उसका अगर औसत निकला जाए तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा।

उन्होंने कहा कि किसान ऊर्जा दाता बनेगा। देश की जनता का भला होगा। देश

■ नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ की सभा में इसके लिए फॉर्मूला स्पष्ट किया कि, पेट्रोल में 60 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की योजना को मूर्त दिया जा रहा है।

■ गडकरी ने इस कार्यक्रम में कहा, अब सब गाड़ियां किसानों के तैयार किए एथेनॉल से चलेंगी। पेट्रोल में 60 प्रतिशत एथेनॉल और 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक इंजन, अगर इसका अगर औसत निकला जाए तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा, और जनता का भला होगा।

का प्रदूषण कम होगा। आयात कम होगा। 16 लाख करोड़ का आयात है। उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। किसानों के घर समृद्ध होंगे। रोजगार मिलेगा। बताते चलें कि इथेनॉल एक अलग तरह का ईंधन है। इसके इस्तेमाल से प्रदूषण कम होता है। गन्ने के रस के जरिये इथेनॉल बनाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर

हरियाणा के पानीपत में टूजी इथेनॉल संयंत्र देश को समर्पित किया था। इस जगह से हर साल तीन करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार की ओर से कहा गया था कि इस परियोजना से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में सालाना लगभग तीन लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर की कमी लाने में योगदान देगी।

# एम.पी में गरीब व्यक्ति पर पेशाब करने के आरोपी का घर ढहाया गया

मध्यप्रदेश प्रशासन ने अमानवीय और बेहद आपत्तिजनक व्यवहार के मामले में कार्रवाई करते हुये आरोपी के मकान का एक तिहाई हिस्सा बुलडोजर से ढहा दिया

सीधो, 5 जुलाई (वार्ता)। मध्यप्रदेश के सीधो जिले में जनजाति समुदाय से आने वाले एक गरीब व्यक्ति पर पेशाब करने के बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय व्यवहार के एक वायरल वीडियो के मामले के आरोपी प्रवेश शुक्ला के अवैध मकान को बुधवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया।

आधिकारिक जांचकर्ता के अनुसार आरोपी प्रवेश शुक्ला के बहरी थाना क्षेत्र के कुबरी गांव स्थित मकान के एक तिहाई हिस्से को प्रशासन ने अवैध मानते हुए बुलडोजर के माध्यम से आवेदन पर एकरतफा सुनवाई के दौरान जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिले में जनजाति समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति के साथ बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय व्यवहार का कल एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कल रात्रि गिरफ्तार कर लिया और आज उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गयी है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुल्बर्गा को भोपाल में सीधी जिले की दुखद घटना के पीड़ित और उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि सीधी की दुखद घटना में पीड़ित एवं उनके परिवारजनों से मुख्यमंत्री चौहान कल यहां सीएम हाउस में मुलाकात करेंगे।

इस बीच सीधी से मिली खबरों के अनुसार पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल करीबी निवासी पीड़ित दशमत रावत के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांडब बंधाया और पुलिस पर पीड़ित को भोपाल

ले जाया गया है। इस मामले को लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्वा ने मध्य प्रदेश में एक युवक के साथ भारतीय जनता पार्टी विधायक के करीबी द्वारा किए गये व्यवहार को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि राज्य में भाजपा के 18 साल के

शासन में आदिवासियों पर अत्याचार हुए हैं। गांधी ने ट्वीट किया, भाजपा-राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। यह भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का ध्वनीना चेहरा और असली चरित्र है। श्रीमती वाड्वा ने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक के एक करीबी द्वारा आदिवासी युवक से की गई अमानवीय व घृणित हरकत बेहद शर्मनाक है। प्रदेश में भाजपा शासन के 18 साल में आदिवासियों पर अत्याचार के 30,400 मामले सामने आए हैं। भाजपा राज में आदिवासी

हिलों पर केवल कोरे दावे और कोरी बातें हैं। आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के असल कदम क्यों नहीं उठाती सरकार।

इस बीच पार्टी ने अपने ट्विटर पेज पर इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा, आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर एक है। साल 2019 में 1,922 मामले, 2020 में 2,401 और 2021 में 2,627 मामलों के आंकड़ों से जाहिर है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार साल दर साल बढ़ रहा है। सनद रह कि ये वो मामले हैं जो तामात अवरोधों के बाद दर्ज हो सके। न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जो पुलिस की फाइलों तक नहीं पहुंचेंगे। पार्टी ने कहा, हाल ही में मध्य प्रदेश के भजपा नेता का एक वीडियो वायरल हुआ। भाजपा नेता ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक आदिवासी युवक के साथ जो क्रुत्य किया गया उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।